वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2020

PRAYOG SAMAJ SEVI SANSTHA

प्रयोग समाज सेवी संस्था
तिल्दा–नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

पृष्ठभूमि –

प्रयोग समाज सेवी संस्था की स्थापना वर्ष 1975 से आरंभ हुआ और पंजीयन वर्ष 1982 में हुआ । **प्रयोग** की पहचान एक ऐसे संस्था के रूप में रही है जिसने ग्रामीण नेतृत्व को विकसित किया है । प्रयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवक युवतियों के लिए 'गांधीयन एक्टीविज्म स्कूल' के रूप में केन्द्र को विकसित किया है । अभी तक 2000 से भी ज्यादा युवाओं को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जो राज्यभर में कार्यरत हैं ।

संस्था द्वारा दलित, आदिवासी एवं भूमिहीनों के लिये किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है –

- आदिवासी और भूमिहीनों को संगठित और एकजुट करना तथा स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाना ।
- शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन की दिशा में जागरूक करना ताकि अधिकाधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनओं का लाभ मिल सके ।
- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन व अपने अधिकारों के प्रति सामूहिक प्रयास करना ।
- संघर्ष, रचना व संवाद के माध्यम से अधिकारों के लिए जागरूक करना ।
- समुदाय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा जल, जंगल, जमीन व आजीविका के अधिकार के लिए सामूहिक पहल करना ।
- जागरूकता निर्माण और मोबिलाईजेशन के विभिन्न पहलुओं जैसे लोक केन्द्रित विकास के लिए जवाबदेह संसाधन प्रबंधन, भूमि वितरण, आदिवासी समाज की जंगल में पहुंच (उपयोग–उपभोग), विकेन्द्रिकृत निर्णयों और सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

संस्थागत कार्यक्षेत्र

संस्था द्वारा वर्ष 2020 में चार राज्यों में व्यापक तौर पर संगठन निर्माण, युवा एवं महिला नेतृत्व निर्माण, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अधिकाधिक हितग्राहियों को खाद्यान्न आपूर्ति व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कार्यक्षेत्र में संचालित समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से **''राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन''**, **''आवासीय भूमि अधिकार कानून''** तथा **''महिला कृषक हकदारी कानून''** को लागू करने जैसे नीतिगत बदलाव की दिशा में प्रयास कर रही है ।

राज्यवार कार्यक्षेत्र का विवरण –

क्र.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लॉक संख्या	पंचायत संख्या	गांव संख्या		
					सघन	सम्पर्क	कुल
1	छत्तीसगढ़	18	23	393	439	292	731
2	मध्यप्रदेश	18	43	472	472	314	786
3	उड़ीसा	09	14	75	225	150	375
4	झारखण्ड	08	16	58	145	97	242
5	बिहार	04	07	27	80	20	100
6	तमिलनाडु	02	03	12	40	10	50
		59	**106**	**1037**	**1401**	**883**	**2284**

संस्थागत स्टॉफ की जानकारी

परियोजना का नाम	कुल कार्यकर्ता	फिल्ड स्तरीय कार्यकर्ता		समन्वयन स्तरीय कार्यकर्ता	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
बी.एम.जेड.–डब्ल्यू.एच.एच. परियोजना (भूमि व जल अधिकार परियोजना)	36	18	12	6	0
बी.एम.जेड–डब्ल्यू.एच.एच. कोविड रिलिफ परियोजना	11	0	0	8	3
ई.यू.–डब्ल्यू.एच.एच. परियोजना (संगठन निर्माण परियोजना)	19	4	9	5	1
सीख कार्यक्रम (यूनिसेफ)	13	5	5	3	0
आदिवासी लाईव मेटर	8	0	0	5	3
सुपोषण (आई.जी.एस.एस.एस.)	5	1	2	2	0
	92	28	28	29	7
कुल महिला	35	38-04%			
कुल पुरूष	57	61.96%			

संस्था की वित्तीय स्थिति – 1 अप्रेल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक

क	दानदाता का नाम	परियोजना अवधि	स्वीकृत राशि	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान प्राप्तियॉ	बैंक से प्राप्त ब्याज	कुल प्राप्तियॉ	कुल खर्च	शेष
1	*बी.एम.जेड.–डब्ल्यू.एच.एच. परियोजना (भूमि व जल अधिकार परियोजना)*	*अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2022*	45200400	868627.74	4915354.29	16737	5800719.03	5162385.52	638333.51
2	*बी.एम.जेड–डब्ल्यू.एच.एच. कोविड रिलिफ परियोजना*	*सितम्बर 2020 से अप्रेल 2021*	26431600	0.00	2782804.48	0.00	2782804.48	2306922.44	475882.04
3	*ई.यू.–डब्ल्यू.एच.एच. परियोजना (संगठन निर्माण परियोजना)*	*जनवरी 2016 से सित. 2020*	44601440	1904624.84	2508809.79	15767	4429201.63	4413456.44	15745.19
4	*सीख कार्यक्रम (यूनिसेफ)*	*जून 2020 से दिसम्बर 2020*	2647000	0.00	2283000.00	0.00	2283000.00	1617667.00	665333.00
5	*आदिवासी लाईव मेटर–1*	*अगस्त 2019 से जुलाई 2020*	3978000	273594.60	678440.00	3373	955407.60	951220.00	4187.60
	आदिवासी लाईव मेटर–2	*अगस्त 2020 से जुलाई 2023*	26640000	0.00	2056420.00	0.00	2056420.00	863065.00	1193355.00
6	*सुपोषण (आई.जी.एस.एस.एस.)*	*अप्रेल 2020 से मार्च 2021*	933800	177106.00	424800.00	4169	606075.00	496298.00	109777.00
7	पी.आई.एच.	*नवम्बर 2019 से दिसम्बर 2020*	1855700	599253.00	580043.00	0.00	1179296.00	472140.00	707156.00
8	केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी	*जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020*	1250000	643615.00	253798.00	0.00	897413.00	137510.00	759930.00
9	सिल्विया इन्टरेस्ट फण्ड		395000	27178.00	0.00	12245.00	434423.00	25000.00	409423.00
10	माया फण्ड		234000	0	0.00	0.00	234000.00	0.00	234000.00
11	जनरल इन्टरेस्ट फण्ड		255668.79	0	0	48246.00	303914.79	401.20	303513.59
	कुल		154422608.79	4493999.18	16483469.56	100537	21962674.53	16446065.6	5516635.93

- वर्ष 2020 की प्रथम सूर्वोदय के समय जय–जगत 2020 के तहत् विश्व–शान्ति का नारा देते हुए एकता परिषद दिल्ली से वर्धा की ओर अग्रसर थे, जिसमें प्रयोग समाज सेवी संस्था के कार्यक्षेत्र से लगभग 15 साथी शामिल रहे हैं । जय–जगत यात्रा जब मध्यप्रदेश से नागपुर होते हुए जब वर्धा, महाराष्ट्र पहुॅची तो कार्यक्षेत्र के सभी राज्यों के लगभग 100 साथी इस वैश्विक शान्ति के यात्रा तथा सम्मेलन में शामिल रहे । यह जय–जगत यात्रा राजघाट, नई दिल्ली से जिनेवा, स्वीटजरलैण्ड तक जा रहा था । इस जय–जगत यात्रा के 4 मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं –
    1. गरीबी उन्मूलन
    2. असमानता मिटाना
    3. जलवायु परिवर्तन
    4. अहिंसा

- वर्धा सम्मेलन के पश्चात् जय–जगत के जिनेवा यात्रियों को अलग–अलग दल में बॉटा गया, जिसमें से तीन दल प्रयोग संस्था के कार्यक्षेत्र में करीब 10–10 दिन रहकर जय–जगत यात्रा के उद्देश्यों को प्रचारित–प्रसारित किये, जिसमें संस्था ने पूरा सहयोग दिया ।

- मार्च 22, 2020 से कोरोना महामारी के चलते देशभर में सम्पूर्ण बंद और लॉकडाउन लम्बे अवधि के लिए जारी किया गया । लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया । कारखाना, दुकान, बाजार, रेल–बस–ऑटो–टैक्सी, होटल–लॉज आदि सभी बंद हो गये । लाखों मजदूर बेकार और बेघर हो गये । धीरे–धीरे पलायन व्यक्ति को लगा कि जैसे–तैसे भी उनका घर वापसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो वे सभी अपने परिवारों को लेकर भूखे–प्यासे पैदल, साईकिल और मंहगी भाड़े की वाहनों में घर वापसी का करूण दृश्य दिल दहलाने वाला था। प्रयोग समाज सेवी संस्था अपने संसाधनों से पलायन मजदूरों को रास्ते में खाना खिलाने का काम किया तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रम किया ।

- गांव में काम के अभाव के कारण जो लोग कष्टमय अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उनके लिए काम के बदले राशन के तहत् राहत कार्य चलाया और इसी के तहत् 45 जिलों में तालाब गहरीकरण, सड़क मरम्मत, कुॅआ सफाई, नाला सफाई आदि का 117 ढॉचा तैयार करते हुए माह जून 2020 तक 4098 लोगों को लगभग 28 लाख रूपये का राशन वितरित किया गया ।

- इस कठिन समय में लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए हमने ग्रामीण युवाओं का शिविर, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चलाया गया । कोविड स्थिति में गांव के लोगों के साथ गांव विकास योजना बनाकर सरकारी अधिकारियों के साथ इन्टरफेस के जरिये संवाद स्थपित किया गया ।

संस्था की प्रमुख उपलब्धियॉं

1. संगठन निर्माण परियोजना – 1 जनवरी 2016 से 30 सितम्बर 2020

समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा को प्रभावी बनाने के लिए भारत में एक मजबूत, जवाबदेह तथा पारदर्शी नागरिक समाज तैयार एक व्यापक उद्देश्य है । जिसका पैमाना यह है कि जल, जंगल और जमीन पर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए दो नीति ''राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति'' तथा ''राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार कानून'' को सरकार द्वारा प्रशासनिक नियमों, आदेशों या नीति के रूप में स्वीकार किया गया हो ।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना के तहत् प्रभावशीलता और पारदर्शिता के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सामाजिक संगठनों तथा ग्रामीण मुखियाओं को सशक्त बनाना, इस परियोजना का उद्देश्य है ।

इस अभियान के तहत् तीन मापदण्डों में कार्य किया गया, जो इस प्रकार है –

1. राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर किये जा रहे विभिन्न अभियान के प्रबंधन में सामाजिक
2. समावेशी तथा विविधता हो ।
3. सदस्य संगठनों के आंतरिक शासन प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन तथा सामाजिक जवाबदेही को
4. सशक्त हो ।
5. प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों के मुद्दों पर जनता को जुड़ाव हो ।

उपलब्धियॉं

- *व्यक्तिगत वनाधिकार* – संगठन निर्माण परियोजना के तहत् उपरोक्त अवधि के दौरान चारों राज्यों के 50 जिलों में वनाधिकार के तहत् 24952 व्यक्तिगत दावे लगाये गये, जिसमें 5366 परिवारों को 10143.10 एकड़ का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है । जिसकी अनुमानित कीमत 26268.95 लाख रूपये है ।

राज्य	जिला	कुल दावे	प्राप्त अधिकार	रकबा (एकड़ में)	रकम (लाख में)
छत्तीसगढ़	17	5375	1780	2432.75	196.46
मध्यप्रदेश	18	12916	2604	5644	25654.50
उड़ीसा	9	1719	329	957.21	85.25
झारखण्ड	6	4942	653	1109.12	332.74
	50	24952	5366	10143.08	26268.95

- *सामुदायिक अधिकार* के तहत् 535 सामुदायिक दावे लगाये गये, जिसमें 77 सामुदायिक अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसका रकबा 2311 एकड़ है । इसकी अनुमानित कीमत 474.30 लाख रूपये की है ।

राज्य	जिला	कुल दावे	प्राप्त अधिकार	सामुदायिक अधिकार के प्रकार	रकबा (एकड़ में)	रकम (लाख में)
छत्तीसगढ़	17	52	2	निस्तारी का अधिकार	760	38.00
मध्यप्रदेश	18	372	70		388	123.90
उड़ीसा	9	52	2		365	73.00
झारखण्ड	6	59	3		798	239.40
	50	535	77		2311	474.3

- *<u>आवासीय भूमि अधिकार</u> के तहत् 9651 परिवारों ने आवेदन किये हैं, जिसमें 3375 परिवारों को 67.56 एकड़ अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 222.64 लाख है ।*

राज्य	जिला	कुल दावे	प्राप्त अधिकार	रकबा (एकड़ में)	रकम (लाख में)
छत्तीसगढ़	17	202	30	7.00	21.00
मध्यप्रदेश	18	7477	3109	51.12	171.62
उड़ीसा	9	1972	236	9.44	30.02
झारखण्ड	6	0	0	0	0
	50	9651	3375	67.56	222.64

- *<u>सदस्यता निर्माण</u> के तहत् कार्यक्षेत्र के 50 जिलों में वर्ष 2020 के दौरान 3878 सदस्य बनाये गये । कुल सदस्यता वर्ष 2015-22962, वर्ष 2016 - 6694, वर्ष 2017- 9146, वर्ष 2018- 6850, वर्ष 2019 - 9360 मिलाकर 58890 हो गया है ।*

राज्य	जिला	सदस्यता - नया सदस्य तथा नवीनीकरण						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	कुल
छत्तीसगढ़	17	6253	2205	2835	3124	2445	1028	17890
मध्यप्रदेश	18	12680	3044	3171	2087	2057	980	24019
उड़ीसा	9	1875	128	1044	817	2578	1020	7462
झारखण्ड	6	2154	1317	2096	822	2280	850	9519
	50	22962	6694	9146	6850	9360	3878	58890

- *<u>मुखिया सशक्तिकरण</u> - परियोजना क्षेत्र के 2034 गांव में 4068 मुखिया चयन कर उन्हें सशक्त बनाया गया, जो परियोजना अवधि के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये हैं ।*
- *<u>स्वयं सेवी संगठन का क्षमता विकास</u> - 18 स्वयं सेवी संस्थाओं का आंतरिक स्वशासन, आर्थिक प्रबंधन, एडवोकेसी, जेण्डर तथा प्रपोजल डेवेलपमेन्ट का प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास किया गया ।*
- *<u>माईक्रोप्लान</u> - 4 राज्यों के 50 जिलों के 100 गांवों का माईक्रोप्लान तैयार कर ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित किया गया ताकि गांव भूमि अधिकार, भूमि विकास के साथ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा वनोपज का अधिकार प्राप्त कर सके ।*
- *<u>मॉडल निर्माण</u> - 58 गांवों को सामुदायिक तथा कृषि, उद्यानिकी तथा पशुपालन विभाग के सहयोग से जैविक खेती, भूमि विकास, साफ-सफाई, शराबबंदी, युवा नेतृत्व, महिला नेतृत्व के माध्यम से मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा सका है ।*
- *<u>नीतिगत जन-वकालत</u> - इस परियोजना के माध्यम से दो महत्वपूर्ण अधिनियम ''राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति'' तथा ''राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार अधिनियम'' को पारित कराने हेतु व्यापक जन-वकालत किया जा सका है ।*

गतिविधियॉं

- ***युवा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण*** – यूरोपियन यूनियन तथा वेल्टहंगरहिल्फ के सहयोग से संचालित संगठन निर्माण परियोजना के तहत् 1 जनवरी 2016 से 30 सितम्बर 2020 तक मध्यप्रदेश के 18 जिले, छत्तीसगढ़ के 17 जिले, उड़ीसा के 9 जिले तथा झारखण्ड राज्य के 6 जिले, कुल 50 जिलों में 57 युवा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 5633 युवक–युवतियों (2306 युवती तथा 3327 युवक) ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।
- ***क्षमता विकास प्रशिक्षण*** के तहत् 20 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नीति विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कानून, जैसे– पंचायती राज अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम, भू–राजस्व संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम, अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि की जानकारी दिया गया, जिसमें 4 राज्यों के 2160 युवक–युवती प्रशिक्षित हुए ।
- ***महिला सशक्तिकरण*** के तहत् 42 महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 4568 महिला तथा 1582 पुरूष, कुल – 6150 सहभागी रहे ।

क्र.	राज्य	जिलों की संख्या	सहभागिता		
			महिला	पुरूष	कुल
1	मध्यप्रदेश	14 ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, उमरिया, दमोह, मुरैना, श्योपुर, सागर, टीकमगढ़, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, सिहोर, झाबुआ	1200	215	1415
2	छत्तीसगढ़	14 नारायणपुर, महासमुन्द, बलरामपुर, राजनांदगांव, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़, मुंगेली	1823	1000	2823
3	उड़ीसा	8 कालाहण्डी, कंधमाल, सुन्दरगढ़, रायगड़ा, खुर्दा, बालॉगीर, जाजपुर, नयागढ़	934	279	1213
4	झारखण्ड	6 पलामू, चतरा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग	611	88	699
			4568	1582	6150

- ***किसान प्रशिक्षण*** – 4 राज्यों में 17 किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कम लागत की खेती, नवीन तकनीकि, जैविक खेती, पशुधन पर प्रशिक्षण किया गया, जिसमें 840 सहभागी (298 महिला तथा 542 पुरूष) रहे ।
- ***समुदाय द्वारा श्रमदान कार्य*** के तहत् वर्ष 2016 से 30 सितम्बर 2020 तक 57 श्रमदान के माध्यम से तालाब गहरीकरण, नाला सफाई, सड़क निर्माण, कुॅआ सफाई आदि कार्य किये गये, जिसमें 5348 लोगों ने 16045 कार्यदिवस कार्य कर अनुमानित लागत 40,11,250/– रूप्ये का कार्य किया गया ।

राज्य	जिले	काम के प्रकार	निर्मित ढॉचा संख्या	हितग्राहियों की संख्या	कुल कार्य–दिवस	अनुमानित लागत (लाख में)
छत्तीसगढ़	8	तालाब गहरीकरण, साफ–सफाई, चेकडेम मरम्मत, सड़क मरम्मत, कुॅआ सफाई, स्टोन पिचिंग	12	2065	6196	15.49
मध्यप्रदेश	18		21	924	2772	6.93
उड़ीसा	9		19	1231	3692	9.23
झारखण्ड	6		5	1128	3385	8.46
	41		57	5348	16045	40.11

- ***श्रमदान शिविर–*** *अप्रेल से जून 2020 के दौरान कोरोनो महामारी के कारण लॉकडाउन होने से गरीब ग्रामीण, मजदूर की वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, इस दौरान संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिले, मध्यप्रदेश के 17 जिले, उड़ीसा के 9 जिले तथा झारखण्ड के 5 जिलों में 117 श्रमदान शिविर का आयोजन कर काम के बदले अनाज के माध्यम से तालाब गहरीकरण, सड़क मरम्मत व निर्माण, नदी–बांध–स्टॉपडेम मरम्मत, कुॅआ सफाई आदि कार्य किये गये, जिसमें 4098 लोगों ने 13464 कार्यदिवस कार्य कर लगभग 27,23,744/– रूपये का कार्य किये हैं।*

राज्य	जिले	काम के प्रकार	निर्मित ढॉचा संख्या	हितग्राहियों की संख्या	कुल कार्य–दिवस	अनुमानित लागत (लाख में)
छत्तीसगढ़	14	तालाब गहरीकरण, साफ–सफाई, चेकडेम मरम्मत, सड़क मरम्मत, कुॅआ सफाई, स्टोन पिचिंग	38	1722	6401	12.95
मध्यप्रदेश	17		41	1026	3206	6.48
उड़ीसा	9		24	950	2310	5.58
झारखण्ड	5		14	400	1547	2.23
	45		117	4098	13464	27.24

राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी

- *जन–सत्याग्रह 2018 में परियोजना क्षेत्र के 18 राज्यों से 11500 सत्याग्रहियों की भागीदारी रही जो वर्ष 2020 में भी अपने अधिकार के अभियान में सक्रिय रहे ।*

कोरोना राहत गतिविधियॉं

जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में कोविड 19 महामारी के भारत दस्तक देने के बाद पूरे संगठनात्मक क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया । लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 2020 को सम्पूर्ण लॉक–डाउन घोषित कर दिया गया । सम्पूर्ण लॉक–डाउन होने से यातायात, कारखाना, सभी प्रकार के दुकान, मेहनत–मजदूरी बंद हो गये । पूरा जन–जीवन स्थिर हो गया । अन्य राज्यों तथा राज्य के भीतर पलायन में गये मजदूर वहीं रह गये । अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी । संक्रमण से बचाव के लिए एक गांव के लोग दूसरे गांव जाने तथा आने पर प्रतिबंध लगा दिये । इस स्थिति में स्वयं–सेवी संगठनों की भूमिका भी बढ़ जाती है ।

प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा भी कोरोना 19 से बचाव हेतु निम्न–लिखित पहल किये गये –

गतिविधि	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	झारखण्ड	उड़ीसा	कुल
एकता परिषद द्वारा तैयार एप्प में पलायन परिवार की जानकारी	84	360	140	1700	2284
भोजन वितरण परिवार	159	0	0	1300	1459
वृद्ध, एकल महिला, विकलांग तथा बिना राशनकार्ड परिवार को पी.डी.एस. में सहयोग	378	1400	40	0	1818
सूखा राशन वितरण	304	2450	56	710	3520

मॉस्क वितरण	875	19000	240	480	20595
पलायन परिवार के लिए यातायात सुविधा मुहैया करवाना	0	0	0	570	570
जागरूकता अभियान	140	160	80	180	560

कोविड राहत श्रमदान कार्यक्रम

क्र	राज्य	जिला	गांव	हितग्राही	कुल कार्य दिवस	रकम	तैयार ढॉचा	काम के प्रकार
1	मध्यप्रदेश	17	41	1026	3206	6,47,612	41	तालाब गहरीकरण, नाला व बांध मरम्मत, कुँआ व ढोरही मरम्मत, सड़क मरम्मत व निर्माण, वृक्षारोपण
2	छत्तीसगढ़	13	38	1722	6401	12,60,682	38	
3	उड़ीसा	9	24	950	2310	5,58,250	24	
4	झारखण्ड	6	14	400	1547	3,23,200	14	
		45	117	4098	13464	27,89,744		

वनाधिकार तथा पेशा पर राजनैतिक संवाद

- विरोधी दल के नेता श्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रयोग में आयोजित भूमि संसद में दिनांक 8-9 फरवरी 2019 को अपने भाषण में बोले थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आये तो वनाधिकार अधिकार कानून तथा पेशा कानून क्रियान्वित करने के लिए प्राथमिकता से विचार करेंगे ।
- 23 अगस्त 2020 को प्रयोग सभागृह में छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग जिलों से आये हुए कार्यकर्ता तथा स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के समक्ष ग्रामीण विकास, पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी वनाधिकार कानून तथा पेशा कानून के बारे में अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए बोले कि इसका क्रियान्वयन के लिए हर तीन महीने में हम आपस में बैठकर समीक्षा करें और आगे की रास्ता निकालेंगे ।
- 4 दिसम्बर 2020 में माननीय राजगोपाल जी के उपस्थिति तथा मार्ग-दर्शन में चल रहे स्वराज शिविर में पहुँचे मान्यवर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने सम्बोधन में स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ हमारे मन, विचार और भावनाओं पर नियंत्रण करें ताकि समाज में मानवीय मूल्यों व आदर्शो का विकास हो सके । हमें ग्रामसभा के महत्व पर भी जागरूक होने की जरूरत है
- 22 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग जिलों से आये हुए कार्यकर्ता तथा स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग के कमिश्नर श्री अलेक्स पॉल मेनन ने प्रयोग आश्रम में अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए पलायन मजदूरों के समस्याओं का समाधान के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालने की बात कहे ।

8-9 फरवरी 2018

संवाद

स्वराज शिविर

संवाद

युवा नेतृत्व शिविर – कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ – 21–23 मार्च 2017

किसान प्रशिक्षण – रायगड़ा, उड़ीसा – 23–24 अक्टूबर 2019

प्रशासनिक संवाद – सागर, मध्यप्रदेश –

जैविक खाद – रायसेन, मध्यप्रदेश

अनाज संकलन – विदिशा, मध्यप्रदेश

युवा नेतृत्व श्रम शिविर – बालाघाट – 11–14 फरवरी 2018

राजगोपाल का छत्तीसगढ़ विधानसभा में शासन तथा प्रशासनिक संवाद 23 जनवरी 2019

कोरानो जागरूकता कार्यक्रम व राहत कार्य

2. भूमि और जल अधिकार परियोजना – 1 जनवरी 2019 से 30 दिसम्बर 2022

जर्मन कोपारेशन व वेल्टहंगरहिल्फे के सहयोग से 1 जनवरी 2019 से यह परियोजना प्रारंभ की गई है । यह परियोजना चार साझेदार संस्थाओं के साथ क्रियान्वित की जा रही है – प्रयोग समाज सेवी संस्था, परमार्थ समाज सेवा संस्थान, आई.ए.व्ही.एच. तथा जनहित विकास संस्थान ।

इस परियोजना का उद्देश्य निम्नानुसार है –

- *लोगों के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए भूमि और पानी के अधिकारों की सुरक्षा करना ।*
- *7 राज्यों में खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा टिकाउ आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सीमांत समूहों की भूमि और पानी के अधिकारों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर मुद्दों का समाधान करना है ।*

उपलब्धियॉं

1 जनवरी 2019 से 30 सितम्बर 2020 तक

- *परियोजना क्षेत्र में 5 राज्यों के 30 जिलों, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले, मध्यप्रदेश के 10 जिले, झारखण्ड के 5 जिले, बिहार के 4 जिले तथा तमिलनाडु के 2 जिले शामिल हैं ।*
- *इन जिलों के 600 गांवों में 1200 सशक्त मुखिया साथी (600 महिला तथा 600 पुरूष) चिन्हित*

किये गये हैं जो संगठनात्मक गतिविधियों को ताकत प्रदान करते हैं ।

- *परियोजना के तहत् महिला, भूमिहीन तथा छोटे किसानों सहित आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र के लक्षित समुदाय के भूमि व जल संसाधनों के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में निम्न–लिखित मापदण्ड निर्धारित किया गया है –*

8000 परिवारों को भूमि अधिकार दिलाना इनमें से लगभग 50% महिलाएॅ होंगी

क.	राज्य	जिला	लक्ष्य	वनाधिकार के तहत अधिकार		आवासीय अधिकार		अधिकार प्राप्त महिला हितग्राही		नये दावे
				परिवार संख्या	रकबा (एकड़)	परिवार संख्या	रकबा (एकड़)	संख्या	रकबा (एकड़)	
1	मध्यप्रदेश	10	3000	1769	4033.85	965	307	465	1150.95	5654
2	छत्तीसगढ़	10	3000	298	506.99	266	8.05	115	120.50	1058
3	झारखण्ड	4	1200	256	357.23	17	1.31	0	0	0
4	बिहार	4	1200	0	0	0	0	0	0	0
5	तमिलनाडु	2	600	326	0	48	0	258	0	200
		30	9000	2649	4898.07	1296	316.36	838	1271.45	6912

250 नये सामुदायिक वन अधिकार दावे लगाये गए

क.	राज्य	जिला	लक्ष्य	लगाये गये कुल दावे	प्राप्त अधिकार पत्र	रकबा
1	मध्यप्रदेश	10	100	89	42	1374
2	छत्तीसगढ़	10	100	30	1	1750
3	झारखण्ड	4	40	11	0	0
4	बिहार	4	40	0	0	0
5	तमिलनाडु	2	20	20	0	0
		30	300	150	43	3124

200 जल श्रोतों का निर्माण/ पुनरूद्धार करना, जिससे 10000 परिवारों तक सामुदायिक जल संसाधन पहुॅच सके

क.	राज्य	जिला	लक्ष्य	तैयार ढॉचा	गांव संख्या	सहभागी संख्या	अनुमानित लागत	ढॉचा के प्रकार
1	मध्यप्रदेश	10	70	46	39	1206	2015000	तालाब, कुऑ, बरसाती नाला
2	छत्तीसगढ़	10	70	25	25	1261	976030	तालाब, कुऑ, बरसाती नाला
3	झारखण्ड	4	28	8	7	240	165400	तालाब मरम्मत
4	बिहार	4	28	1	1	40	85000	तालाब
5	तमिलनाडु	2	14	0	0	0	0	
		30	210	80	72	2747	3241430	

परिणाम 2: भारत के विभिन्न हिस्सों से अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को उपयोग करते हुए भूमि और जल प्रबंधन के मॉडल तैयार करना, जो सात राज्यों के ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के द्वारा बर्ना गई है ।

कानूनी साक्षरता के माध्यम से विभिन्न कानूनों की जानकारी के आधार पर भूमि अधिकार के लिए 5,00,000 परिवारों को संवेदनशील बनाना

क.	राज्य	जिला	लक्ष्य	सहभागी संख्या	गतिविधि/ कार्यक्रम
1	मध्यप्रदेश	10	170000	69667	जय जगत यात्रा, जन–सुनवाई, युवा शिविर, ग्रामीण बैठकें, रैली, ज्ञापन
2	छत्तीसगढ़	10	170000	8550	
3	झारखण्ड	4	68000	5600	
4	बिहार	4	68000	11613	

5	तमिलनाडु	2	34000	2735	
		30	510000	98165	

राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर के 200 सरकारी अधिकारियों को भूमि तथा जल संसाधनों के अधिकार के लिए कानूनी और प्रशासनिक रूप से संवेदनशील बनाना

क्र.	राज्य	जिला	लक्ष्य	सम्पर्क अधिकारियों की संख्या	विभाग
1	मध्यप्रदेश	10	70	40	वन विभाग, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय
2	छत्तीसगढ़	10	70	35	वन विभाग, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय
3	झारखण्ड	4	28	7	ग्रामीण विकास, भूमि विकास, मत्स्य
4	बिहार	4	28	11	राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई विभाग, श्रम संसाधन विभाग, कृषि विभाग
5	तमिलनाडु	2	14	6	वन विभाग, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, सांसद, विधायक
		30	210	99	

500 सहभागी गांवों का भूमि, वन और जल उपयोग पर ग्राम विकास योजना तैयार करना और इन योजनाओं को साकार करने के लिए स्थानीय प्रशासन को सौंपना

क्र.	राज्य	जिला	लक्ष्य	कार्य पूर्ण	ग्राम विकास योजना के मुद्दे	वस्तु स्थिति	
						स्वीकृत	प्रक्रिया में
1	मध्यप्रदेश	10	170	58	जल संरक्षण	58	0
2	छत्तीसगढ़	10	170	17	जल संरक्षण	17	0
3	झारखण्ड	4	68	15	नाला व तालाब मरम्मत	15	0
4	बिहार	4	68	10	जल संरक्षण	10	0
5	तमिलनाडु	2	34	22	टाईगर रिजर्व से नगरपालिका क्षेत्र में स्थानान्तरित करने बाबत्	0	22
		30	510	122		100	22

- सदस्यता अभियान

क्र.	राज्य	जिला	लक्ष्य	1 जनवरी 2019 से 30 सितम्बर 2020 तक		
				गांव सं.	सदस्य सं.	सदस्यता राशि
1	मध्यप्रदेश	10	4000	200	6792	65220
2	छत्तीसगढ़	10	4000	116	1801	18010
3	झारखण्ड	4	1600	49	790	7900
4	बिहार	4	1600	46	940	9400
5	तमिलनाडु	2	800	40	550	5500
		30	12000	451	10873	106030

- ग्रामकोष एवं अनाज कोष

क्र.	राज्य	जिला	लक्षित ग्राम संख्या	ग्राम कोष		अनाज कोष	
				ग्राम सं.	राशि	ग्राम सं.	अनाज (क्विंटल में)
1	मध्यप्रदेश	10	200	161	53350	153	92-01
2	छत्तीसगढ़	10	200	89	426880	85	139.21
3	झारखण्ड	4	80	49	32500	49	8.00
4	बिहार	4	80	43	96023	37	21.26

5	तमिलनाडु	2	40	0	0	0	0
		30	600	342	608753	324	168.47

गतिविधियॉं

जर्मन कापरेशन व डब्ल्यू.एच.एच. नई दिल्ली के सहयोग से 1 जनवरी 2019 से परियोजना प्रारंभ हुआ है । जनवरी 2019 से सितम्बर 2020 तक निम्न–लिखित गतिविधियॉ संचालित की गई :–

- **युवा नेतृत्व शिविर**

क.	राज्य	जिला	स्थान	अवधि	सहभागी			
					गांव	महिला	पुरूष	कुल
1	छत्तीसगढ़	कोरिया,	जरडोल	21-23 Jun 2019	16	32	55	87
2	मध्यप्रदेश	मुरेनाा	जौरा	28-30 Jun 2019	18	53	44	97
3	छत्तीसगढ़	कोण्डागांव	पाटला	28-30 Dec 2019	14	30	55	85
4	मध्यप्रदेश	सिहोर	माथर	18-20 February 2020	21	25	82	107
5	मध्यप्रदेश	सगर	हुल्दन	15-18 February 2020	11	22	80	102
6	मध्यप्रदेश	सिवनी	खूट खम्हरिया	1-3 February 2020	16	3	60	63
7	मध्यप्रदेश	झाबुआ	रतिमाली	23-24 February 2020	11	24	74	98
8	छत्तीसगढ़	कोरिया	जरडोल	16-18 March 2020	15	24	56	80
9	छत्तीसगढ़	गरियाबंद	कोदोपाली	6-8 March 2020	17	60	45	105
10	छत्तीसगढ़	धमतरी	सोनझरी	22-24 February 2020	14	28	65	93
11	छत्तीसगढ़	कांकेर	हरिहरपानी	26-28 February 2020	13	40	50	90
12	बिहार	जमुई	स्चखोदेवरा	15-17 Feb 2020	15	26	61	87
13	बिहार	जहानाबाद	औदनबीघा	28-29 Feb & 1st March 2020	18	46	29	75
14	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	पोलीची	28-29 Feb & 1st March 2020	11	50	60	110
					210	463	816	1279

Preparation of village development plans by the communities.

- We have conducted a three days camp on village level community micro planning, where different tools like resource mapping, chapati diagram, transect work and analysis of different government programme like MGNRGA, Swatchh Bharat Abhiyan, Public health and engineering (Toilet) and NRHM through external resource person.
- 3 no's of micro development planning camps were conducted in 3 districts of Madhya Pradesh – Sihore, Sagar & Sheopur districts. Total number of participatnts were 171(Female- 66 + Male-105)

State	District	Village	Dates	No's of villages covered	Female	Male	Total
Madhya Pradesh	Sagar	Pithoriya	12-13 January 2020	9	27	35	62
Madhya Pradesh	Sihore	Aamajhari	15-17 February 2020	19	13	39	52
Madhya Pradesh	Sheopur	Chetikheda	12-14 March 2020	22	26	31	57
				50	66	105	171

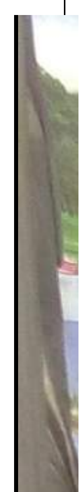

Organize "Shramdan Camps" for reconstruction and conservation of common property resources in the villages.

- During the corona period, we under took shramdan camps and created 8 structures in 5 districts of 3 states, that is Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The total community people participated in Shramdan camps were 284 (female-156 and male 138). These structures were built up in common land. During shramdan we were maintaining the covid guide line.

State	District	Village	Type of work	No's of beneficiaries			Estimated cost of Work
				Female	Male	Total	
Chhattisgarh	Koriya	Tartora	Pond deepening	22	6	28	28,280.00
Chhattisgarh	Koriya	Jolgi	Pond deepening	22	7	29	29,290.00
Chhattisgarh	Jashpur	Khutera	Pond deepening	28	7	25	25,250.00
Chhattisgarh	Jashpur	Sonar pahari	Pond deepening	12	13	25	25,250.00
Chhattisgarh	Surajpur	Charpara (Saraipara)	Pond deepening	17	15	32	32,320.00
Jharkhand	Giridih	Birhor tanda	Pond deepening	13	32	45	45,450.00
Jharkhand	Giridih	Turiyatola	Pond deepening	29	31	60	60,600.00
Bihar	Gaya	Goverdaha (Banwasi Nagar)	Pond deepening	13	27	40	40,400.00
3	**5**	**8**	**1**	**156**	**138**	**284**	**286,840.00**

Interface dialogue amonst community, elected respresentatives and officials on grievances and possible solutions.

- 4 number of interface were conducted in Madhya Pradesh & Bihar in 2019. But, during the 1st & 2nd quarter of 2020 interface program could not be conducted, because of Jai Jagat yatra and its follow up activities. Due to lockdown situation, we could not take up the interfaces in 2nd quarter also.

State	District	Place	Dates	Parcipation			
				No's of village	Female	Male	Total
Bihar	Gaya	Gaya	22 Jul 2020	25	95	115	210
Madhya pradesh	Morena	Morena	24 Jul 2020	82	276	274	550
Madhya Pradesh	Sehore	Budni	6 Dec 2020	41	98	81	179
Madhya Pradesh	Sagar	Sagar	18 Dec 2020	37	126	72	198

				185	595	542	1137

3. शिक्षा का अधिकार ''सीख'' कार्यक्रम

बच्चों के लिए सीखने की गतिविधियों (6–10 वर्ष) में माता–पिता की भागीदारी को सिक्ट प्लेटफॉर्म पर साझा की गई शिक्षण गतिविधियों और संसाधनों के माध्यम से मजबूत किया गया है ।

1. माता–पिता/ परिवारों की संख्या जो घर पर बच्चों के साथ सीखने की गतिविधियों तक पहुॅच रहे हैं –

जिला	ब्लॉक	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल परिवार	सम्पर्क किया गया
रायपुर	तिल्दा	80%	80%	14758	11806
दंतेवाड़ा	गीदम	60%	60%	4628	2777
नारायणपुर	नारायणपुर	60%	45%	8620	3879

2. अपने माता–पिता और देखभाल करने वाले अभिभावकों के सहयोग से सीख प्लेटफॉर्म पर सीखने की गतिविधियों तक पहुॅचने और उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या –

जिला	ब्लॉक	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल परिवार	सम्पर्क किया गया
रायपुर	तिल्दा	70%	80%	17840	14272
दंतेवाड़ा	गीदम	60%	60%	7643	4585
नारायणपुर	नारायणपुर	60%	45%	10204	4592

लर्निंग सेंटर (सीख केन्द्र) सामुदायिक स्तर के स्वयं–सेवकों (सीख मित्र) द्वारा स्थापित किया गया है ।

1. स्थापित सीख केन्द्रों की संख्या

जिला	ब्लॉक	लक्ष्य	उपलब्धि
रायपुर	तिल्दा	100	310
दंतेवाड़ा	गीदम	100	184
नारायणपुर	नारायणपुर	100	174

2. सीख मित्रों की संख्या जिनके द्वारा कोविड 19 के लिए बनाये गये नियमों का पालन करते हुए सीख केन्द्रों में छोटे–छोटे समूह बनाकर बच्चों को सीखने में मदद किया जा रहा है

जिला	ब्लॉक	लक्ष्य	उपलब्धि
रायपुर	तिल्दा	200	450
दंतेवाड़ा	गीदम	200	425
नारायणपुर	नारायणपुर	200	280

4. आदिवासी लाईव्स मेटर परियोजना

आदिवासी समाज देश दुनिया में अपना प्रतिनिधित्व, अपनी संस्कृति को स्थापित करे, यही आदिवासी लाईव्स मेटर का उद्‌देश्य है । भारत में आदिवासी अनुसूचित जनजाति देश की आबादी का 8.6% है, कल 104 मिलियन लोग हैं, जो कि दुनिया की स्वदेशी आबादी का 40% है । भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों के साथ, जो 500 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, आदिवासियों की विविधता को चित्रित नहीं किया गया है । उचित और पर्याप्त, न तो मीडिया या समाचार में, न ही कला और साहित्य की दुनिया में । आदिवासियों का प्रतिनिधित्व और नैतिक चित्रण, नीतिगत चर्चाओं में ही नहीं, बल्कि आदिवासियों की पहचान और उपस्थिति को स्थापित करने के लिए मुख्यधारा की, समाज की बातचीत में भी महत्वपूर्ण है । लेखक, फिल्म निर्माता और पर्यटक आमतौर पर उन्हें बर्बर, पुराने, पिछड़े या विदेशी लोगों के रूप में चित्रित करते हैं । यह देश के कुछ सबसे पुराने निवासियों की पहचान की पुष्टि करने के उद्‌देश्य से काम नहीं करता है ।

आदिवासी लाईव्स मेटर का उद्‌देश्य है आदिवासी को अपनी पहचान दिलाना । आदिवासी युवा, आदिवासी युवाओं द्वारा डिजिटल कहानियों के माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए आदिवासी लाईव्स मैटर (एएलएम) और प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा एक परियोजना है ।

आदिवासी लाईव्स मैटर एक आदिवासी केन्द्रित मीडिया पहल है जो 2016 में भारत भर के आदिवासी डिजिटल कहानीकारों को सलाह देने और संवारने के लिए शुरू हुई थी । यह प्रयोग समाज सेवी संस्था, छत्तीसगढ़ की एक परियोजना है, जो 1982 में एक जमीनी स्तर पर संगठन शुरू हुआ और भारत भर के भूमिहीन और बेघर लोगों के साथ–साथ आदिवासियों के भूमि–अधिकारों पर काम कर रहा है ।

उपलब्धियाँ भविष्य के लक्ष्य

	लक्ष्स	उपलब्धियाँ
राष्ट्रीय ऑनलाईन पोर्टल नागरिक पत्रकारों द्वारा तैयार की जाने वाली सामग्री प्रकाशित करना	10	3
भारत के 5 राज्यों में आदिवासी सामग्री रचनाकारों को प्रशिक्षित करना	150+	125+
सोशल मीडिया समर्थकों और एएलएम के अनुयायियों को संलग्न करना	105,000+	21500+
राष्ट्रीय मीडिया हाउस नागरिक पत्रकारों द्वारा तैयार की जाने वाली सामग्री प्रकाशित करना	25	5
मूल और अनन्य सामग्री के टुकड़े जिनमें फोटो कहानियाँ, लेख और वीडियो तैयार करना	2000+ ‘	300+
एएलएम द्वारा मूल और अनन्य सामग्री के लिए डिजिटल कहानीकारों पर खर्च करना	2	1
सोशल मीडिया चैनलों पर ऑनलाईन इंप्रेशन	55,000,000+	7,100,000+

5. सुपोषण

सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के 25 गांवों के लिए परियोजना में काम करने की योजना बनाई गई है । मैनपाट छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पिछड़े ब्लॉक में से एक है जो सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाली आदिवासी आबादी के प्रभुत्व में है । इन क्षेत्रों में पहाड़ी कोरवा पीटीजी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दशकों में गंभीर रूप से खराब हुई है । लगभग 90% कामकाजी आबादी कृषि पर निर्भर करती है । उनमें से अधिकांश को छोटे भूमि जोत मिले हैं लेकिन पूरी तरह से मानसून की वर्षा पर निर्भर है, जिसमें शून्य सिंचाई की सुविधा है । इसके अलावा उनके पास बाजार में क्रय कम शक्ति है और इसलिए वे ऋणग्रस्तता की स्थिति में है । इन सभी से महिलाओं और बाल स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं । 6 - 59 महीने के आयु वर्ग के लगभग 36.3% बच्चे कम वजन वाले और 5 साल से कम उम्र के 22.6% बच्चे विकृतियों में कुपोषित हैं ।

इस परियोजना में निम्न उद्देश्यों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से काम किया गया –

1. विशेष रूप से पांच वर्ष से कम उम्र बच्चों और महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए
   - लक्ष्य परिवारों से 70% कुपोषित बच्चों को CBO द्वारा उपचार लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजना ।
   - लक्ष्य परिवारों को 80% लाभार्थी पोषण सघन फसलों और छोटे पैमाने पर पशुधन के उत्पादन के माध्यम से अधिक विविध भोजन उपलब्ध करवाना ।
2. विविध और नवीन आजीविका विकल्पों को अपनाने के माध्यम से छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों की आय में वृद्धि करवाने के लिए
   - लक्ष्य परिवारों से 80% छोटे किसान लाभार्थी अपनी आय 10% & 15% बढ़ा सकना ।
3. समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम है
   - 12 समुदाय आधारित संगठन सीबीओ प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारी, अनुकूलन और शमन उपाय करना ।
4. आजीविका और विकास पर समुदाय आधारित संगठनों को स्थानीय पंचायती राज पर भागीदारी सुनिश्चित करना

Indicators	Units	Target	Achievements
70% of malnourished children have been referred to Nutrition Rehabilitation Cenres for treatment and follow up by CBOs	No. of Children	194	68
80% of beneficiaries eat more diverse food through production of nutrition dense crops and small scale livestock	No. of Beneficiary families	1811	355
The rates of woter borne diseases in the community are reduced by 80% through positive behavior change on issues related to sanitation, water usage and waste management	No. of Beneficiary families	1811	348
80% of smallholder farmer beneficiaries could increase their income by 10-15%	No. of Beneficiary families	2105	426
75% of landless beneficiaries could increase their income by 10-15%	No. of Beneficiary	37	13

	families		
20 innovative enterprises are initiated and consolidate to generate income enhancement in groups	No. of Enterprise	1	0
1125 community based organizations (CBOs) take up preparedness, adaptation and mitigation measures to reduce the impact of natural hazards and climate change events.	No. of CBOs	10	1
Community owned degraded area is rehabilitated by CBOs (the percentage is determined after collection of the baseline data)	Hectares of land	22	9
More and more hectares of land are irrigated through water conservation/ recharge measures (the percentage is determined after collection of the baseline data)	Hectares of land	8	0
There is one CBO per village or cluster of villages which actively participates in local governance exercises.	No. of CBOs	10	4
There is one CBO per village or cluster of villages which monitors the receipt of food and wage related entitlements by the communities.	No. of CBOs	10	3
Amount of resources mobilized from the government for development work by community organizations (cannot be quantified as it depends on the authorities)	Rupees	160 Lakhs	70 Lakhs

आई.जी.एस.एस.एस. सुपोषण परियोजना के अन्तर्गत कोविड 19 के तहत् किये गए कार्यो इस प्रकार है –

- **हाथ धुलाई जागरूकता अभियान का विस्तार लक्ष्य परिवारों तक पहुॅचाई गई** – आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और मुखिया साथियों के साथ मास्क लगाकर सामाजिक दूरी रखते हुए कोरोना महामारी के लिए जागरूकता अभियान चलाते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में पिछले सत्र में अलग–अलग गांवों में हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किये गये थे । इसी कार्यक्रम विस्तार पूर्वक घर–घर जाकर प्रतिदिन व्यवहार में लाने के लिए समझाईस दी गई । इसके लिए हाथ धुलाई के 6 चरणों में हाथ धोने की विधि बताई गई । अपने घरों में सुरक्षित रहकर एकदम जरूरी काम पड़ने पर मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए कहते हुए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के आदेशों का पालन करने के लिए बताया गया । इसके तहत् अभी तक 1082 परिवारों तक इस जागरूकता के लिए पहुॅच बनाई जा सकी है ।
- **परियोजना के लक्ष्य परिवारों तक सूखा राशन और आंगनबाड़ी हितग्राहियों तक रेडी–टू–ईट पहुॅचाने में सहयोग किया गया** – लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी करने वालों के पास खाने–पीने हेतु समस्याएॅ आ गई, जिन्हें समस्याग्रस्त परिवारों को चिन्हित कर शासन के योजना अनुसार 5 कि.ग्रा. चॉवल, 15 कि.ग्रा. दाल, तेल, प्याज और आलू भी साथ में वितरण करने में कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग किया गया । आंगनबाड़ी हितग्राहियों को रेडी–टू–ईट विशेषकर कुपोषित बच्चों तक पहुॅचाने में सहयोग के साथ घरों में उपलब्ध मुनगा, उसकी भाजी के साथ आस–पास मिलने वाली हरी साग–सब्जियां खाने में उपयोग किया जाय, जिससे परिवार के सदस्यों की रोग–प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे । इसके तहत् 215 स्कूली बच्चों और

आंगनबाड़ी के 118 हितग्राहियों तक लाभ पहुँचाई गई ।

- **पलायन से वापस आये परिवारों के साथ लक्ष्य परिवारों को मनरेगा में पंजीकृत कर कामगारों को काम दिलवाने में मदद की गई** – परियोजना के लक्ष्य परिवारों के अलावा पलायन से वापस आये परिवारों को मनरेगा में काम करने के लिए पंजीयन कर सुपोषण परियोजना से संबंधित जलाशयों की खुदाई और गहरीकरण तथा वनाधिकार से प्राप्त भूमि समतलीकरण आदि कार्यों में रोजगार के साथ सीधे कामगारों के हाथों में मजदूरी भुगतान करने में हमारे कार्यकर्ताओं ने पंचायत सचिव व रोजगार सहायक के माध्यम से सहयोग किया । इसके तहत् 268 परिवारों को रोजगार दिलाने में सहयोग किया गया ।
- **परियोजना क्षेत्र में क्वारेंटाईन सेंटर में सहयोग** – कोरोना महामारी के चलते क्वारेंटाईन सेंटरों में सहयोग के तहत् ग्राम जामपानी तथा ग्राम पंचायत जजगा के जामडीह मोहल्ले में एक–एक कोरोना संक्रमित पाया गया था जिसे स्वस्थ होने के बाद क्वारेंटाईन सेंटर में रहा जो निश्चित समयावधि 14 दिन के बाद होम आइसोलेशन में रहा । इसके अलावा इस क्षेत्र में पलायन से वापस आये 7 मजदूरों को भी क्वारेंटाईन सेंटर में रखा गया । इस दौरान हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के सारे उपाय बताकर समझाए ।

6. कोविड 19 राहत अभियान – 1 सितम्बर 2020 से 30 अप्रेल 2021

कोविड महामारी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में लघु व सीमांत किसान तथा ग्रामीण मजदूरों के हाथ में काम न होना, आगे भूखमरी होने का शंका है । अपने तरफ से थोड़ा–बहुत मदद करने के उद्देश्य से डब्ल्यू.एच.एच और बी.एम.जेड. नई दिल्ली की सहायता से अब 6 राज्यों में 36 जिलों में बीज वितरण, पोषण बेड, बकरी पालन, तालाब गहरीकरण, कुँआ सफाई, नाला–बांध मरम्मत के साथ साथ हेण्ड–पम्प मरम्मत का काम प्रारंभ हो गया है ।

गतिविधि का नाम	राज्य का नाम	जिला का नाम	गांव संख्या	हितग्राही संख्या	अनुमानित रकम
सीड किट वितरण	उड़ीसा	कालाहण्डी	3	60	102000.00
		बालॉगीर	4	55	93500.00
		सुन्दरगढ़	4	50	85000.00
		खुर्दा	4	55	93500.00
		रायगड़ा	1	20	34000.00
		4	**16**	**240**	**408000.00**
	छत्तीसगढ़	कोरिया	2	60	102000.00
		गरियाबंद	2	60	102000.00
		धमतरी	4	60	102000.00
		सूरजपुर	2	60	102000.00
		4	**10**	**240**	**408000.00**
	मध्यप्रदेश	धार	3	60	102000.00

		दमोह	3	60	102000.00
		2	**6**	**120**	**204000.00**
		1 0	**32**	**600**	**1020000.00**

पोषण बागवानी	उड़ीसा	कालाहण्डी	5	25	35000.00
		कंधमाल	2	20	28000.00
		बालॉगीर	2	20	28000.00
		नयागढ़	2	20	28000.00
		खुर्दा	3	20	28000.00
		4	**14**	**105**	**147000.00**
	छत्तीसगढ़	जशपुर	2	35	49000.00
		सरगुजा	2	35	49000.00
		कोरिया	1	35	49000.00
		3	**5**	**105**	**147000.00**
	मध्यप्रदेश	सिवनी	4	40	56000.00
	बिहार	गया	1	30	42000.00
	झारखण्ड	कोडरमा	1	30	42000.00
		हजारीबाग	1	30	42000.00
		2	2	60	84000.00
		1 1	26	340	476000.00
बकरी पालन	उड़ीसा	कंधमाल	4	5	42500.00
		कालाहण्डी	1	5	42500.00
		2	5	10	85000.00

अरूण कुमार)
सचिव